Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 ◘ अंक- 213 ◘ रायपुर, सोमवार 8 दिसंबर 2025 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

आईएएस अधिकारियों को कैडर आवंटित, छग को मिले 3 आईएएस

रायपुर, 8 दिसंबर (हाईवे चैनल)। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी-सीएसई 2024) के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया है. ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को होम स्टेट कैडर उत्तर प्रदेश मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ को इस बार 3 नए आईएएस मिले हैं. यूपीएससी 2024 में 65 वीं रैंक हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस पूर्वा अग्रवाल को झारखंड कैडर मिला है। छत्तीसगढ़ को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी मिले हैं. गोकुल आरके ने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में 424 रैंक हासिल किया. वी. यशवंथ ने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में 424 रैंक हासिल किया. वहीं इशांत जायसवाल ने 441 रैंक हासिल किया है।

इंडिगो का परिचालन संकट बरकरार, प्रमुख हवाई अड्डों पर 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (न्यूज चैनल)। इंडिगो में जारी परिचालन संकट अभी भी जारी है। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर सोमवार को भी इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं और उनमें देरी हो रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने सोमवार को सुबह साढ़े छह बजे यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और एडवाइजरी में बताया कि उड़ानों में देरी हो सकती है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक जरूर करें ताकि एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना न करना पड़े। सोमवार को 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं हैं, जिनमें अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह 8 बजे तक इंडिगो की 18 उड़ानें रद्द हुईं। बंगलूरू हवाई अड्डे पर 127 उड़ानें रद्द हुईं हैं। वहीं हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 77, दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 उड़ानें रद्द हुई हैं। चेन्नई, अहमदाबाद और असम के एयरपोर्ट्स पर टर्मिनल एरिया में भारी भीड़ है। इस तरह बीते करीब एक सप्ताह में इंडिगो की करीब चार हजार उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे देश का हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार के दखल के बावजूद अभी तक हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। इंडिगो एयरलाइन ने डीजीसीए के नोटिस का जवाब देने के लिए और समय देने की मांग की है। डीजीसीए ने शनिवार 6 दिसंबर को इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें इंडिगो के परिचालन संकट पर जवाब मांगा गया था। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ और अकाउंटेबल मैनेजर पोर्केरास को जारी नोटिस में कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन योजना बनाने की असफलता और संसाधन प्रबंधन की चूक दिखाई देती है।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, इंडिगो की रोज सैकड़ों उड़ाने रद्द हो रही है।
चुहिया- हां जी, सरकार भी तो आसमान में उड़ रही थी।

जमीन की गाइड लाइन दरों पर बड़ा बदलाव सरकार ने कई आदेश लिए वापस

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में हुआ क्या निर्णय

रायपुर, 8 दिसंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय- नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया. अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10 प्रतिशत कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25 प्रतिशत कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है. जिला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें। उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभावशील होंगे।

जरूरत पड़ी तो करेंगे बदलाव: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।

बाइक-स्कूटी के बीच हुई जोरदार भिड़ंत युवक और बुजुर्ग की मौके पर मौत

रायपुर/आरंग, 8 दिसंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र की नगर पंचायत समोदा में आज बाइक और स्कूटी के आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था की दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही आरंग पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा।

आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि हादसा समोदा-कुसमुंद रोड पर नहर के पास हुआ। बाइक बजाज एवेंजर (क्रमांक सीजी 04 एमबी 5669) पर ग्राम सुंदावन, थाना पलारी जिला बलौदाबाजार निवासी उमेश कुर्रे (19 वर्ष) सवार था। दूसरी ओर स्कूटी एक्टिवा (क्रमांक सीजी 04 एलएस 4191) ग्राम तुलसी, थाना खरोरा निवासी तिहारूराम साहू (60 वर्ष) चला रहे थे। हाई-स्पीड में विपरीत दिशा से आ रहे दोनों वाहनों की नहर के पास जोरदार भिड़ंत हो गई, टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और चालकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरंग थाना टीम ने घटनास्थल पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मर्चुरी भेजा।

पुलिस के अनुसार, दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार तेज रफ्तार और सड़क के संकरे हिस्से पर अचानक सामने आ जाने से यह दुर्घटना हुई हो सकती है। घटना से दोनों गांवों में शोक का माहौल है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

मणिपुर में 3 उग्रवादी गिरफ्तार, कारतूस जब्त

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर (न्यूज चैनल)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार तथा गोला-बारूद का बड़ा जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस बयान के अनुसार, रविवार को बिष्णुपुर जिले के नगाईखोंग खुल्लेन इलाके से जबरन वसूली में शामिल प्रतिबंधित संगठन पीआरईपीएके (पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक) के एक उग्रवादी को पकड़ा गया। उसके पास से दो बंदूकें, 13 कारतूस, एक हथगोला और दो वॉकी-टॉकी सेट जब्त किए गए। जबरन वसूली में शामिल प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (कोइरेंग) का एक सक्रिय सदस्य भी रविवार को इंफाल पश्चिम जिले के कडंगबंद से गिरफ्तार किया गया है।

सीसी मेंबर रामधेर ने 11 साथियों के साथ किया आत्मसमर्पण

तीन राज्यों में नक्सली नेटवर्क को लगा करारा झटका

खैरागढ़, 8 दिसंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता दर्ज करते हुए सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. यह सरेंडर आज सुबह गांव कुम्ही, थाना बकर कट्टा में किया गया, जहां सभी कैडरों ने हथियार नीचे रखकर पुलिस के सामने खुद को समर्पित किया. इस कदम को सुरक्षा एजेंसियां नक्सली ढांचे पर निर्णायक प्रहार मान रही हैं, क्योंकि यह पूरा समूह एमएमसी—महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़—स्पेशल जोनल कमेटी का सक्रिय हिस्सा था, जो तीन राज्यों के छह जिलों में अपनी पैठ बनाए हुए था। रामधेर मज्जी द्वारा एके-47 के साथ आत्मसमर्पण किए जाने को नक्सली संगठन की सबसे बड़ी टूट मानी जा रही है. उसके साथ डीवीसीएम रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी सरेंडर किया, जिनमें से दो के पास-च-47 और इंसास जैसे हथियार मौजूद थे. इनके अलावा एसीएम स्तर के नक्सली रामसिंह दादा और सुकेश पोट्टम ने भी हथियार डाले, जबकि क्षेत्रीय महिला मिलिशिया की लक्ष्मी, शीला, योगिता, कविता और सागर ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया. समूह के पास एके-47, इंसास, एलएलआर, 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद हुए हैं।

इस सरेंडर ने एमएमसी स्पेशल जोन को लगभग निष्प्रभावी बना दिया है. इससे पहले एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत गोंदिया में आत्मसमर्पण कर चुका था, जबकि बीते एक दिन में ही बालाघाट में सुरेंद्र सहित नौ अन्य माओवादी हथियार डाल चुके हैं।

नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को बनाया बंधक, मौके से जान बचाकर सुरक्षा कैम्प पहुंचा सहयोगी

बीजापुर, 8 दिसंबर (हाईवे चैनल)। जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को बंधक बना लिया है। घटना के दौरान नक्सलियों द्वारा ठेकेदार के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी मिली है। शुरूआती जानकारी के मुताबिक ठेकेदार इम्तियाज अली के साथ काम कर रहे उसके एक सहयोगी ने किसी तरह मौके से जान बचाकर भागने में सफलता पाई। वह सीधे इरापल्ली के मेटागुड़म कैंप पहुंचा, जहां उसने पूरी घटना की जानकारी सुरक्षा बलों को दी।

ठेकेदार इम्तियाज अली के सहयोगी ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान नक्सलियों का एक दस्ता मौके पर पहुंचा और ठेकेदार को अपने साथ जंगल की ओर ले गया। मामले की पुष्टि करते हुए बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया, ठेकेदार के साथ काम करने वाला उसका एक साथी हमारे कैंप में पहुंचा है। उसने बंधक बनाए जाने की जानकारी दी है। हमारी टीमें घटना की तस्दीक कर रही हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस और सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नक्सलियों ने ठेकेदार को किस उद्देश्य से उठाया है। गौरतलब है कि सड़क निर्माण कार्य लंबे समय से नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि ये परियोजनाएँ नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की आवाजाही और विकास कार्यों को गति देती हैं। इसी कारण ठेकेदारों और मजदूरों पर नक्सली दबाव व हमलों की घटनाएँ समय-समय पर सामने आती रहती हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें ठेकेदार की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने में जुटी हैं। घटना पर आगे के अपडेट का इंतजार है।

वंदे मातरम् भाव जैसी दुनिया के इतिहास में कहीं पर रचना नहीं : मोदी

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि जो वंदे मातरम् 1905 में महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था। वंदे मातरम् इतना महान था, इसकी भावना इतनी महान थी तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वह कौन-सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावना पर भारी पड़ गई जिसने वंदे मातरम् जैसी पवित्र भावना को विवादों में घसीट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि-कोटि जनों को प्रेरित करता हो... पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे, यह विश्व के लिए अजूबा है।

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि बंगाल का विभाजन तो हुआ लेकिन बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन हुआ और तब वंदे मातरम् हर जगह गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम बाबू का यह भाव सूत्र जो उन्हीं तैयार किया था उसने अंग्रेजों को हिला दिया था। इस गीत की ताकत इतनी थी कि अंग्रेजों को इस गाने पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ा था।

मुख्यमंत्री साय ने मध्यप्रदेश में नई सिंचाई तकनीक 'प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क' की प्रस्तुति का किया अवलोकन

छत्तीसगढ़ में भी इस तकनीक के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा: मुख्यमंत्री

रायपुर, 8 दिसंबर (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने आज भोपाल में सिंचाई की नवीनतम तकनीक पीआईएन के संबंध में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों की तुलना में यह प्रणाली कहीं अधिक कुशल, आधुनिक और जल संरक्षण के अनुरूप है। अपर मुख्य सचिव राजौरा ने प्रस्तुति के दौरान बताया कि जहाँ पारंपरिक नहर आधारित सिंचाई में लगभग 35 प्रतिशत एफिशिएंसी प्राप्त होती है, वहीं प्रेशर इरिगेशन प्रणाली में दक्षता बढ़कर 65 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। इस तकनीक में प्रेशर आधारित पाइपलाइनों से सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का रिसाव और अपव्यय कम होता है तथा बिजली की उल्लेखनीय बचत होती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रणाली में भू-अधिग्रहण की आवश्यकता न्यूनतम होती है, जिससे परियोजनाएं समय पर और लागत प्रभावी तरीके से पूरी की जा सकती है।

प्रस्तुति में उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तकनीक से सिंचाई की जा रही है और आगामी वर्षों में इसे 40 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। इस मॉडल से न केवल जल उपयोग दक्षता बढ़ी है, बल्कि किसानों की उत्पादकता और सिंचाई सुविधा में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रेजेंटेशन की सराहना करते हुए कहा कि सिंचाई की यह उन्नत तकनीक जल प्रबंधन की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है। उन्होंने कहा, हम इस तकनीक का छत्तीसगढ़ में भी अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि राज्य के किसानों को कम पानी में अधिक सिंचाई सुविधा और बेहतर उत्पादन मिल सके। जल संरक्षण, ऊर्जा बचत और त्वरित क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से यह तकनीक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस तकनीक के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किए बिना भी सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभागीय अधिकारियों को इस तकनीक के अध्ययन, परीक्षण और चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद देवड़ा, अधीक्षण यंत्री विकास राजोरिया और अधीक्षण यंत्री शुभंकर विश्वास भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक नहर आधारित सिंचाई में पानी का एक बड़ा हिस्सा रिसाव, वाष्पीकरण और अनियंत्रित बहाव के कारण व्यर्थ हो जाता है, जिससे खेतों तक वास्तविक जल आपूर्ति सीमित रहती है और पूरी कमांड एरिया में समान सिंचाई नहीं हो पाती। सामान्यत: पारंपरिक प्रणाली की कुल सिंचाई दक्षता केवल 35 प्रतिशत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर पीआईएन प्रणाली में पानी पाइपलाइनों के माध्यम से नियंत्रित दबाव के साथ सीधे खेतों तक पहुँचाया जाता है, जिससे पानी का अपव्यय लगभग शून्य हो जाता है। इस तकनीक से सिंचाई दक्षता बढ़कर 65 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, जो जल संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीआईएन प्रणाली में सिंचाई पूरी तरह पाइपलाइन आधारित होने के कारण नहर निर्माण की आवश्यकता कम हो जाती है और भू-अधिग्रहण भी न्यूनतम होता है। इससे परियोजनाओं की लागत घटती है और कार्य समय पर पूरे होते हैं।

नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से

रायपुर, 8 दिसंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक नए विधानसभा भवन में चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विजन 2047 के अनुसार सरकार काम कर रही है। सरकार सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। हमारी सरकार सोने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल उपलब्धियों से भरे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कम समय में मोदी गारंटी को पूरा किया और सभी विभागों को पर्याप्त बजट मिल रहा है। दो साल में छत्तीसगढ़ काफी बदल चुका है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्वागतसभी के लिए जरूरी है, यह समाज के हित में है। कांग्रेस के पास कोई कार्य योजना नहीं है। अपनी अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है।